

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 831
07 फरवरी, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए
पुरानी मिलों के पुनरुद्धार हेतु योजनाएं

831. श्री विनायक भाऊराव राऊत:

श्री ओम पवन राजेनिंबालकर:

श्री संजय जाधव:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार परभणी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित देश के मिल कामगारों को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से अनेक पुरानी मिलों के पुनरुद्धार के लिए कोई योजनाएं कार्यान्वित कर रही है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) उक्त बेरोजगार कामगारों के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं;
- (घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महाराष्ट्र के सोलापुर जिले की बर्शी टेक्सटाइल मिल्स के साथ-साथ महाराष्ट्र की कई अन्य मिलें कोविड के कारण 2020 से बंद हो गई हैं जिसके परिणामस्वरूप कई मिल कामगार बेरोजगार हो गए हैं;
- (ङ) क्या मजदूर संघों और क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने उक्त मिलों के पुनरुद्धार के लिए सरकार से कई बार संपर्क किया है परन्तु अभी भी मिलों का पुनरुद्धार नहीं किया जा सका है; और
- (च) यदि हां, तो उक्त वस्त्र मिलों को पुनः चालू करने और बेरोजगार कामगारों को रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और क्या भूमिका निभाई गई है?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्रीमती दर्शना जरदोश)

(क) से (च): भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कोविड-19 महामारी के कारण घोषित राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण सोलापुर जिले में बार्शी टेक्सटाइल मिल्स के साथ महाराष्ट्र की कई अन्य मिलों सहित सभी एनटीसी मिलों की उत्पादन गतिविधियाँ मार्च, 2020 से रोक दी गई थीं। जनवरी, 2021 से कुछ एनटीसी मिलों में सामान्य प्रचालन पुनः शुरू किया गया था, लेकिन कार्यशील पूंजी की अनुपलब्धता और अन्य वित्तीय बाधाओं के कारण इसे जारी नहीं रखा जा सका। कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य बकाये के भुगतान हेतु आवश्यक कार्रवाई की गयी है।

फरवरी, 2021 में, आत्मनिर्भर भारत के लिए एक नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (पीएसई) नीति की घोषणा की गई, जो पीएसई के लिए एक व्यापक रोडमैप तैयार करती है। व्यय विभाग (डीपीई) द्वारा जारी किए गए गैर-रणनीतिक क्षेत्र में सीपीएसई के लिए नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (पीएसई) नीति के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार, एनटीसी का मुद्दा कार्य योजना और भावी योजना के लिए डीपीई को भेजा गया है।
